

सेवा में

1. महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. मा० प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड जिला देहरादून
4. मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, जिला देहरादून
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय जिला देहरादून
6. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय जिला देहरादून

विषय - उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जनपद में अनुसूचित जनजाति अंतर्गत जौनसारी अनुसूचित जनजाति के वास्तविक जातियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी न कर अविधिक रूप से सवर्ण तथा अगड़ी जातियों यथा ब्राह्मण, राजपूत क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियों के लोगो को जौनसारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं उन्हें आर्थिक लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

लोक सभा में 12 अगस्त 1967 को Bill.no.119 of 1967 The SC & ST orders (Amendment) Bill. 1967 पेश किया गया जिसके पेज संख्या 71 The Schedule Uttar Pradesh पेज 5 क्रम सं० 8 Jaunsari (excluding khasa Jaunsari viz Brahmin and Rajput) में यह प्राविधान किया गया था इसी प्रकार C.B (II) no 236 Lok Sabha The SC & ST orders (Amendment) Bill. 1967 Report of The Joint Committee) Presented On The 17 November 1969 Chapter v Uttar Pradesh क्रम 2 Bhil For the-existing tribe Jaunsari (excluding Khasa Jaunsari viz Brahmin and Rajput The Following tribes have been Substituted अर्थात् देहरादून जनपद के जौनसार बावर परगना एवं उत्तरकाशी गढ़वाल के जौनपुर परगना में प्राविधान था पेज संख्या 46 The Following tribes Jaunsar Bawar क्रम संख्या 18, Bajgi, Auji, Chanorm Beda, Darzi, Dhake, Diyad, Hurkiya, Turi Nai Jhumaria 19, Barhai, Badi, Mistri, Ode 20.Chamar 21.Chura, 22. Dhaliya, 23.Dom, Doom, 24.Jogi, Jogra, Nath, 25.Julaha, Varav, 26. Koli, Koi, 27.Kolta, 28. Kumhar, 29.Luhar, 30. Pari, 31.Ruriya, 32.Sunar 33. Tamta जाति के लोगों का ही अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का प्राविधान था।

महोदय अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पहला पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर कालेलकर आयोग, 1953) ने अनुसूचित जनजातियों को इस रूप में परिभाषित किया है वे एक अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों की मुख्य धारा में पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए हैं। वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं उक्त के पश्चात निम्न समितियों के द्वारा अपनी सिफारिश दी गयी थी। उक्त के क्रम भारत गणराज्य के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग देश की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में हिस्सेदारी करें यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से विशेष रूप से जनजातिय (जनजातीय) समुदायों को पिछले छह दशकों में कार्यान्वित विकास परियोजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला है बल्कि इस अविध के दौरान कार्यान्वित विकास परियोजनाओं का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

एलविन कमेटी (1959) का गठन सभी जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिये बुनियादी प्रशासनिक इकाई बहु उद्देश्यीय विकास खंड (मल्टी पर्पज डेवलपमेंट ब्लॉक) के कार्यक्रमों की जाँच के लिये किया गया था।

यु.एन. डेबर आयोग का गठन वर्ष 1960 में जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजातीय समूहों की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिये किया गया था।

लोकुर समिति (1965) का गठन अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड पर विचार करने के लिये किया गया था समिति ने उनकी पहचान के लिये पाँच मानदंडों आदिम लक्षण विशिष्ट संस्कृति भौगोलिक अलगाव बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन की सिफारिश की। उक्त समिति की रिपोर्ट के पश्चात नोटिफिकेशन संख्या 107 जारी होने की तिथि दिनांक 24 जून 1967 [No.F.19 (2)/66-LI] जारी किया गया था जिसमें 4 अन्य जनजातियों के साथ 'जनसारी' को भी अनुसूचित जनजाति के रूप में क्रम संख्या 3 पर सम्मिलित किया गया था।

महोदय लोकुर कमेटी ने जौनसारी अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या-41 के अपेंडिक्स-4 में यह स्पष्ट रूप से यह तथ्य लिखा था कि:

16- JAUNSARI A polyandrous tribal group residing in the Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi districts. They are isolated, and backward. There are however some forward groups, viz. Bralunins and Rajputs, who are being excluded. Estimated population 56,000.

लोकुर कमेटी की उक्त रिपोर्ट को आधार बना कर ही भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या-107 [No. F. 19 (2)/66-LI] दिनांकित 24-जून-1967, जिसे तत्कालीन सचिव श्री एस.पी. सेन वर्मा के हस्ताक्षरों से जारी किया गया था उक्त नोटिफिकेशन को जारी किये जाते समय "जूनसारी" अनुसूचित जनजाति में अगड़ी जाति के ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समुदाय को "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित नहीं किया गया है।

महोदय उपरोक्त विषय के क्रम में प्रार्थी अवगत कराना है कि भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या-107 [No. F. 19 (2)/66-LI] दिनांकित 24-जून-1967, जिसे तत्कालीन सचिव श्री एस.पी. सेन वर्मा के हस्ताक्षरों से जारी किया गया था। उक्त गजट नोटिफिकेशन में "जनसारी" को क्रम संख्या-3 पर अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। उक्त गजट नोटिफिकेशन में "जनसारी" अनुसूचित जनजाति में देहरादून जिले के कालसी, चकराता एवं लूनी तहसील तथा टिहरी गढ़वाल जनपद की जौनपुर तहसील तथा उत्तरकाशी में निवास करने वाली निम्नलिखित जातियों को "जनसारी" अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था जिनका जातिवार (कुल वार) विवरण निम्नवत है।

1. Bajgi 2. Auji 3. Chanao 4. Beda 5. Darzi 6. Darji 7. Dhake 8. Diad 9. Hurkiya
10. Tur 11. Nai 12. Jhumaria 13. Barhai 14. Badi 15. Mistri 16. Ode 17. Chamar
18. Chura 19. Dhaliya 20. Dom / Dome 21. Jogi/Jogra/Nath
22. Julaha/Varaw 23. Koli/Kol 24. Kolta 25. Kumhar 26. Luhar 27. Pari 28. Ruriya
29. Sunar 30. Tomota 31. Bhil

महोदय भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या-107 जारी होने की तिथि दिनांक 24-जून-1967 [No. F. 19 (2)/66-LI] में "जौनसारी" को क्रम संख्या-3 पर अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, उक्त गजट नोटिफिकेशन में "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति में देहरादून जिले के कालसी, चकराता एवं त्यूनी तहसील तथा टिहरी गढ़वाल जनपद की जौनपुर तहसील में निवास करने वाली उपरोक्त वर्णित 31 जातियों (कुल) को ही "जौनसारी अनुसूचित जनजाति अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। उक्त गजट नोटिफिकेशन जारी होने के उपरान्त से स्थानीय प्रशासन के द्वारा मनमाने रूप से वर्तमान तिथि तक "जनसारी" अनुसूचि, जनजाति के प्रमाण पत्र केवल देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाली तीन तहसीलो यथा कालसी, चकराता और त्यूनी तहसील के निवासियों को ही जारी किये जा रहे हैं, टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाले उपरोक्त 31 जातियों (कुल) के व्यक्तियों को "जनसारी" अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं जबकि क्षेत्र की उपरोक्त वर्णित 31 जातियां ही न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े तथा समाज में एक अलग स्थान रखने के कारण "जनसारी" जनजाति में सम्मिलित की गयी थी। जिसके चलते वर्तमान में उपरोक्त वर्णित 31 जातियों के लोगो को न केवल सरकारी नौकरियों से वंचित होना पड़ रहा है बल्कि उन्हें भारत सरकार की योजनाओं का भी पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। अविधिक रूप से उच्च कुल के लोगो यथा ब्राह्मण एवं राजपूत जाति के लोगो के द्वारा जौनसारी जनजाति का प्रमाण पत्र अविधिक रूप से प्राप्त कर लेने के चलते सरकारी नौकरियों में भी उनका अधिपत्य हो गया है और वे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस तथा पीपीएस जैसे अनेक उच्च पदों पर उनका अधिपत्य हो गया है और उक्त पदों पर आसीन होने के चलते वे उपरोक्त वर्णित 31 जातियों के साथ भेदभाव भी करते हैं।

महोदय उपरोक्त विषय के क्रम में आप प्रेषितगण महोदयों को यह भी अवगत कराना है कि देहरादून जनपद के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मनमाने रूप से बिना किसी अधिकारिता के आम जनमानस में इस प्रकार का भ्रम पैदा किया गया है कि जनपद देहरादून की कालसी, चकराता एवं त्यूनी तहसील का क्षेत्र जो स्थानीय स्तर पर "जौनसार बावर" के नाम से भी जाना जाता है, को भारत सरकार के द्वारा "जनजाति क्षेत्र" घोषित किया हुआ है और जौनसार क्षेत्र में निवास करने वाला चाहे वह अगड़ी जाति का ही क्यों न हो जौनसारी जनजाति का माना जाएगा, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की उक्त मनमानी व्याख्या के चलते उक्त देहरादून जिले की उक्त तीन तहसील क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जोशी, डोभाल, शर्मा, भट्ट, डिमरी, नौटियाल, बहुगुणा, पाण्डे, उनियाल, थपलियाल, सेमवाल, बिजल्वाण, भारद्वाज, सारस्वत आदि अगड़ी जातियों तथा राजपूत कुल में उत्पन्न चौहान, रावंत, नेगी, तोमर, पंवार, राणा, बिष्ट, रमोला, असवाल, कुंवर, सजवाण, भण्डारी, गुसाईं, राठोर आदि तथा वैश्य कुल में उत्पन्न अगड़ी जातियों के व्यक्तियों को "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बिना किसी व्यक्ति की वास्तविक जाति (कुल) का भौतिक सत्यापन किये उपरोक्त नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से ही अद्यतन तक अविधिक एवं मनमाने रूप से लगातार जारी किये जा रहे हैं, जबकि उच्च एवं अगड़ी जाति के ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकारिता भी नहीं रखते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान के अंतर्गत 'पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र' (Fifth Schedule Areas) ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे प्रावधानित है और उक्त के क्रम में वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में पाँचवीं अनुसूची के तहत क्षेत्र विद्यमान हैं, उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी क्षेत्र उक्त

12

अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। साथ ही जनपद टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जनपद के स्थानीय प्रशासन के द्वारा उपरोक्त नोटिफिकेशन जारी होने की तिथी तक "जौनसारी" जनजाति की प्रमाण पत्र, पात्र 31 जातियों के लोगो को जारी नहीं किये जा रहे हैं।

महोदय स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त वर्णित नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात सन 2024 तक के लगभग उच्च कुलीन ब्राम्हण, राजपूत तथा वैश्य जैसे अगड़ी जातियों के उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, ऐसे कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के क्रम में प्रशासन के द्वारा उनके नाम के साथ लगाने वाली उनकी वास्तविक उच्च कुल की जाति (कुल) के नाम को छिपा कर अविधिक रूप से "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, वर्ष 2000 के पश्चात से स्थानीय प्रशासन ने पूर्व में किसी पिता को जारी किये गए जनजाति के प्रमाण पत्र को आधार मान कर उनके पुत्र एवं पुत्रियों को जारी किये गये प्रमाण पत्र में उनके नाम के आगे जनजाति के प्रमाण पत्र भी अद्यतन लगातार निर्गत किये जा रहे हैं, जबकि ब्राह्मण, राजपूत एवं वैश्य कुल की जातियों का उल्लेख कर "जौनसारी" अनुमति सरकार के द्वारा उपरोक्त नोटिफिकेशन में "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति में अगड़ी जाति के ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित भी नहीं किये गये हैं।

महोदय स्थानीय प्रशासन के उक्त विधि विरुद्ध कृत्य से न केवल वास्तविक रूप से "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित उपरोक्त वर्णित 31 जातियों (कुल) के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं आरक्षण के लाभों से भी वंचित होना पड़ रहा है साथ ही पिछले कई वर्षों से उपरोक्त वर्णित 31 जातियों (कुल) के लोगो को विधानसभा एवं विभिन्न स्थानीय निकायों में उनके उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व से भी वंचित किया जा रहा है।

महोदय प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थिति से राज्य सरकार भी परिचित है, और वह इस स्थिति को रोकना भी चाहती थी, जिसके चलते राज्य सरकार के तत्कालीन प्रमुख सचिव ने अपने पत्रांक संख्या-D.O. NO.1312/FRDC/2001 दिनांकित 28-08-2001 के द्वारा राज्य सरकार के मंतव्य से भी भारत सरकार को अवगत कराते हुए "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत निर्गत किये जाने वाले जनजाति के प्रमाण पत्रों में "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के स्थान पर निम्न वर्णित 31 जातियों (कुल) के नाम से ही अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव भी भेजा था, जिनका विवरण निम्नवत है :-

1. Bajgi 2. Auji 3. Chanao 4. Beda 5. Darzi 6. Darji 7. Dhake 8. Diad 9. Hurkiya 10. Tur 11. Nal 12. Jhumaria 13. Barhal 14. Badi 15. Mistri 16. Ode 17. Chamar 18. Chura 19. Dhaliya 20. Dom/Dome 21. Jogi/Jogra/Nath 22. Julaha / Varaw 23. Koli/ Koi 24. Kolta 25. Kumhar 26. Luhar 27. Pari 28. Ruriya 29. Sunar 30. Tomota 31. Bhil

उपरोक्त के होते हुए भी उत्तराखण्ड में अद्यतन अगड़ी उच्च जाति के ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जाति के लोग अविधिक रूप से "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं, और यह सब कुछ सरकार में उच्च पदों पर आसीन कतिपय अधिकारियों के प्रभाव के चलते हो

रहा है, जिस पर आज दिनांक तक भी न तो भारत सरकार ने, न ही उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने ही कोई रोक लगाई है, जिसके चलते आज दिनांक तक उपरोक्त वर्णित 31 जातियों (कुल) के वास्तविक "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के लोगो के बजाय क्षेत्र में निवास करने वाले अगड़ी जाति के ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य कुल में उत्पन्न लोगो को अविधिक रूप से "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कर उपरोक्त 31 अति पिछड़ी जातियों के वास्तविक जौनसारी समुदाय के लोगो को उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन किया जा रहा है। महोदयगण के संज्ञान हेतु 08-2001 एंव उसके साथ संलग्नक-1 की छायाप्रति संलग्नक संख्या-1 के रूप उत्तराखण्ड राज्य सरकार पत्रांक संख्या D.O. NO.1312/FRDC/2001 दिनांकित 20 पृष्ठों में संलग्न है।

महोदय यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि अविधिक रूप से जौनसारी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उच्च कुल के ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जाति के लोग राजकीय योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति के लोग बन कर लेते हैं लेकिन क्षेत्र के आम समाज और व्यवहार में वे अपने को उपरोक्त वर्णित 31 जातियों के लोगो से अपने को उच्च कुल का बता कर उनके साथ घोर भेदभाव का व्यवहार करते हैं। जिसके चलते उपरोक्त वर्णित 31 जातियों के लोगों की समाज में स्थिति अत्यंत ही दीन हीन बनी हुई है।

महोदय भारत में किसी जाति एंव कुल को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार एकमात्र रूप से भारत सरकार को है एंव भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच पड़ताल एंव आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किये जाने हेतु वर्ष 1975 के पश्चात से समय समय पर राज्य सरकारों के प्राधिकारियों को अपने विभिन्न आदेशों के द्वारा दिशा निर्देश एंव जनजाति के प्रमाण पत्र जिस प्रारूप में निर्गत किये जायेंगे इस हेतु भी दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं, लेकिन जनपद देहरादून के तहसील कालसी, चकराता एंव त्यूनी में स्थानीय प्रशासन के द्वारा "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने में न केवल गंभीर अनियमितता की जा रही है बल्कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने के क्रम में भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन न कर मनमाने रूप से उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य कुल के कुलीन व्यक्तियों की अपनी जांच। सत्यापन आख्या एंव प्रमाण पत्र में उनकी उच्च जाति (कुल) को छिपा कर विधि विरुद्ध रूप से "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा घोषित "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति की उपरोक्त वर्णित 31 जातियों में सम्मिलित नहीं हैं। महोदय उक्त स्थिति के दृष्टिगत नोटिफिकेशन संख्या-107 जारी होने की तिथि दिनांक 24-जून-1967 [No. F. 19(2)/66-LI] से इस प्रत्यावेदन के प्राप्त होने की तिथी तक जनपद देहरादून के कालसी, चकराता एंव त्यूनी तहसील से जारी समस्त, "जनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों के सापेक्ष प्राप्त समस्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जा कर उपरोक्त वर्णित 31 जातियों (कुल) के अतिरिक्त अगड़े उच्च कुलीन यथा ब्राह्मण, राजपूत एंव वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को अविधिक रूप से जारी किये गए "जनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों को उनके निर्गत किये जाने की तिथी से निरस्त किया जाना आवश्यक है ताकि भारत सरकार के द्वारा "जनसारी" अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित उपरोक्त वर्णित 31 जातियों (कुल) के व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का वास्तविक लाभ प्रदान किये जाने के साथ संविधान प्रदत्त उनके

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हितों को संरक्षित रखा जा सके और उन्हें उच्च कुलीन जातियों के व्यक्तियों के द्वारा किये जा रहे अन्याय एवं अत्याचार से भी मुक्ति दिलाई जा सके ।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में आप प्रेषितगण समस्त महोदयगण से प्रार्थी की न्यायहित में विनम्र प्रार्थना है कि :-

1-भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की सलाह से आदेश पारित किया जिसकी फोटोप्रति संलग्न है, उल्लेखनीय है कि महामहिम राष्ट्रपति ने निम्न पांच समुदाय को जनजाति (ST) आदेश दिनांक 24-06-1967 द्वारा घोषित किया गया जो कि निम्न प्रकार है :-

1-भोटिया 2-बोक्सा 3-जनसारी 4-राजी 5-थारू

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश में क्रम संख्या 3 पर शब्द "जनसारी" को प्रिंटिंग से "जौनसारी" छाप दिया गया है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है किसी भी आदेश से जौनसार बाबर क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन संख्या-107 [No. F. 19(2)/66-LI] दिनांकित 24-जून-1967 को उत्तराखण्ड राज्य सरकार के प्रस्ताव पत्रांक-संख्या- D.O. NO.1312/FRDC/2001 दिनांकित 28-08-2001 में वर्णित उपरोक्त 31 जातियों (कुल) के नाम से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु पूर्व के नोटिफिकेशन को संशोधित कर भारत सरकार के द्वारा नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाय।

2. जनपद देहरादून की कालसी, चकराता एवं त्यूनी तहसील अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन संख्या-107 [No. F. 19(2)/66-LI] दिनांकित 24-जून-1967 के क्रम संख्या-3 में उल्लेखित "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथी से अब तक निर्गत समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन / जांच राज्य सरकार की संस्थ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाय।

3. भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-107 [No. F. 19(2)/66-दिनांकित 24-जून-1967 के क्रम संख्या-3 में उल्लेखित "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथी से सत्यापन / जांच किये जाने की तिथी तक अगड़ी जाति के ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य जाति (कुल) में उत्पन्न व्यक्तियों को अविधिक रूप से जारी "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के समस्त प्रमाण-पत्रों को उनके जारी होने की तिथी से निरस्त किया जाय।

4. जनपद देहरादून की कालसी, चकराता एवं त्यूनी तहसील अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन संख्या-107 [No. F. 19(2)/66-LI] दिनांकित 24-जून-1967 के क्रम संख्या-3 में उल्लेखित "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथी से सत्यापन / जांच किये जाने की तिथी तक अगड़ी जाति के यथा ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य जाति (कुल) में उत्पन्न व्यक्तियों को अविधिक रूप से जारी "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्रों को जारी करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही आपराधिक वाद पंजीकृत करवाया जाय।

5. भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-107 [No. F. 19(2)/66-LI] दिनांकित 24-जून-1967 के क्रम संख्या-3 में उल्लेखित "जौनसारी" अनुसूचित जनजाति के स्थान पर "जौनसारी" अनुसूचित

11

जनजाति में सम्मिलित जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी की अति पिछड़ी एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से जीवन यापन करने वाले वाले उपरोक्त वर्णित 31 जातियों (कुल) के व्यक्तियों को ही अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

यह कि इसके सम्बन्ध में लोकसभा में प्रश्न भी पूछे गए थे जो कि निम्न है :-

1. लोकसभा प्रश्न संख्या 786 (12 दिसम्बर 2022)

विषय: Number of Tribal Communities

इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में 700+ अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित हैं।

सूची State/UT-specific होती है यानी एक राज्य में ST मानी जाने वाली जाति दूसरे राज्य में ST न भी हो सकती है। नई जनजाति जोड़ने/निकालने या संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है:

राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, फिर Registrar General of India (RGI) और NCST से अनुमोदन, उसके बाद संसद में विधायी संशोधन।

उत्तराखंड: Annexure में साफ़ लिखा है Uttarakhand = 05 ST entries. यानि, 1967 के बाद भी उत्तराखंड में सिर्फ 5 जनजातियाँ ही अनुसूचित हैं (भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू)। कोई नई प्रविष्टि नहीं हुई।

2. Annexure (तालिका – राज्यवार ST संख्या)

Annexure की तालिका में हर राज्य/UT के सामने ST प्रविष्टियों की संख्या है।

Uttarakhand = 05 लिखा हुआ है।

तुलना के लिए: Himachal Pradesh = 10, Uttar Pradesh = 15, Odisha = 62, Maharashtra = 45 आदि।

उत्तराखंड: केवल पाँच जनजातियाँ मान्य हैं।

3. लोकसभा प्रश्न संख्या 5167 (4 अप्रैल 2022) ST Status of H.P. and Uttarakhand

इसमें संविधान का प्रावधान (अनुच्छेद 244) और अनुसूचित क्षेत्र (5th Schedule) व जनजातीय क्षेत्र (6th Schedule) की प्रक्रिया समझाई गई है। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया गया (Trans-Giri area को Scheduled Area बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, पर मानदंड पूरे न होने से अस्वीकृत हुआ)।

"As per available record neither the 'Scheduled Areas' under Article 244(1) of Fifth Schedule of the Constitution, nor the 'Tribal Areas' under Article 244(2) of Sixth Schedule of the Constitution have been notified in the State of Uttarakhand so far."

उत्तराखंड में अब तक कोई Scheduled Area (अनुसूचित क्षेत्र) या Tribal Area घोषित ही नहीं हुआ है।

1. अनुसूचित जनजातियाँ: उत्तराखंड में आज भी केवल 5 प्रविष्टियाँ हैं —

भोटिया (जाड़, जौहारी, माना, मार्चा, नीति-वाल, शौका, तोल्छा आदि उपनामों सहित) बुक्सा, जौनसारी

राजी (बनरावत/बनमानुष), थारू

(1967 से अब तक इसमें कोई नई जनजाति नहीं जोड़ी गई है)।

2. अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area): उत्तराखंड में आज तक एक भी Scheduled Area अधिसूचित नहीं है।

3. 1967 के बाद बदलाव: न तो कोई नई ST जनजाति जोड़ी गई, न ही कोई Scheduled Area अधिसूचित हुआ।

महोदय के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन उल्लेखित तथ्यों पर अविलम्ब संज्ञान लेते हुए जौनसारी अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित उपरोक्त वर्णित 31 जातियों कुल के संविधान प्रदत्त हितों को संरक्षित रखने एवं उनके प्रति सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से हो रहे घोर अन्याय एवं अत्याचारों से मुक्ति दिलाये जाने हेतु अविलम्ब रूप से त्वरित कार्यवाही की जायेगी और प्रार्थी को भी उसके इस प्रत्यावेदन के प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर की गयी कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

धन्यवाद

दिनांक: 06-09-2025

प्रार्थी



विकेश सिंह नेगी (एडवोकेट)

चैम्बर नम्बर 1 ए, विपरीत शाहेद स्मारक

सिविल कोर्ट कंपाउंड, जिला न्यायालय

जिला देहरादून -248001

मो०-9758222922

¹[THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) (UTTAR PRADESH) ORDER, 1967

(C.O. 78)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Uttar Pradesh, is pleased to make the following Order, namely:--

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.
2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution of India, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

- | | |
|---|---|
| 1. Bhotia | 8. Saharya (in the district of Lalitpur) |
| 2. Buksa | 9. Parahiya (in the district of Sonbhadra) |
| 3. Jannasari | 10. Baiga (in the district of Sonbhadra) |
| 4. Raji | 11. Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur) |
| 5. Tharu. | 12. Agariya (in the district of Sonbhadra) |
| ² [6. Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jompur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra) | 13. Patari (in the district of Sonbhadra) |
| 7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra) | 14. Chero (in the districts of Sonbhadra and Varanasi) |
| | 15. Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra)]. |

1. Published with the Ministry of Law, Notifn. No. G.S.R. 960, dated the 24th June, 1967, Gazette of India, Extraordinary, 1967, Part II, Section 3(i), page 311.

2. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO- 5167
TO BE ANSWERED ON- 04/04/2022

ST STATUS OF H.P. AND UTTARAKHAND

167. SHRIMATI PRATIBHA SINGH:

Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the Trans Gori Area of Himachal Pradesh has been granted the status of Tribal Affairs;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the State Government of Himachal Pradesh has taken up this matter with Union Government;
- (d) if so, the details thereof;
- (e) whether it is a fact that Jaunsai-Bawar of Uttarakhand has been granted the status of Tribal Area; and
- (f) if so, whether the tribals of Sirmour district of Himachal Pradesh are still deprived off the status despite the entire area being part of Sirmour Princely State if so, the reasons therefor?

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR TRIBAL AFFAIRS
(SHRI BISHWESWAR TUDU)**

(a) to (d) : The provisions of Article 244 of the Constitution enables designation of certain areas as Scheduled and Tribal Areas and for their administration. The Constitution provides for two types of areas, areas designated as "Scheduled Areas" in terms of Fifth Schedule of the Constitution and areas designated as 'Tribal Areas' in terms of Sixth Schedule of the Constitution. According to the Constitutional provision of Fifth Schedule under Article 244 (1) of the Constitution of India the expression "Scheduled Areas" means such areas as the President may by order declare to be Scheduled Areas. Specification of a Scheduled Area or modification of an existing Scheduled area is done after consultation with the Governor of that State and through notification issued with the approval of the President of India. The "Tribal Areas" are designated in terms of Article 244(2) of the Constitution of India read with Sixth Schedule of the Constitution of India.

The State Government of Himachal Pradesh submitted a proposal for notifying entire Trans-Giri area of Sirmour district, Dodra Kwar Sub-Division of Shimla district, 15/20 areas of Shimla and Kullu districts as Scheduled Areas in Himachal Pradesh. For declaration of Scheduled Areas the criteria followed are - preponderance of tribal population, compactness and reasonable size of the area, a viable administrative entity such as a district, block or taluk, and economic backwardness of the area as compared to neighboring areas.

The proposal was examined in the Ministry and could not be considered due to want of requisite criteria, as mentioned above. Accordingly, the State Government of Himachal Pradesh was intimated that the proposal in the current form for declaration of Scheduled Areas could not be considered.

(e): As per available record neither the "Scheduled Areas" under Article 244(1) of Fifth Schedule of the Constitution, nor the "Tribal Areas" under article 244(2) of Sixth Schedule of the Constitution have been notified in the State of Uttarakhand so far.

(f): Same as mentioned against (a) to (d) above.

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO- 1786
TO BE ANSWERED ON- 12/12/2022**

NUMBER OF TRIBAL COMMUNITIES

1786. SHRI MALOOK NAGAR:

Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the number of tribal communities identified in the country, State-wise;
- (b) whether the Government has any proposal to include more castes/communities in the list of Scheduled Tribes; and
- (c) if so, the details thereof?

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR TRIBAL AFFAIRS
(SHRI BISHWESWAR TUDU)**

(a): There are over 700 Scheduled Tribes notified under Article 342 of the Constitution of India, spread over different States and Union Territories (UT) of the country. Many tribes are notified in more than one State/UT. The list of Scheduled Tribes is State/UT specific and a community declared as a Scheduled Tribe in a State, need not be so in another State/UT. Number of Scheduled Tribe communities State/UT-wise identified in the country is annexed at Annexure.

(b) & (c): The Government of India has approved the modalities for deciding the claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the Orders specifying lists of Scheduled Tribes. According to these modalities, only those proposals which have been recommended and justified by the State Government/UT Administration concerned, can be processed further. Thereafter, it has to be concurred with by the Registrar General of India (RGI) and the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) for consideration for amendment of legislation. All actions are taken as per these approved modalities.

Proposals for inclusion and other amendments in the list of Scheduled Tribes of any State are processed in accordance with these modalities, which is an ongoing process.

Annexure referred to in reply to part (a) of Lok Sabha Unstarred Question No. †786 to be answered on 12.12.2022

State/UT wise number of Scheduled Tribes.

Sl	Name of State/UT	Number of entries of Scheduled Tribes.
1	Andhra Pradesh	34
2	Arunachal Pradesh	All tribes including 15 specifically mentioned.
3	Assam	29
4	Bihar	32
5	Chhattisgarh	42
6	Goa	08
7	Gujarat	29
8	Himachal Pradesh	10
9	Jammu and Kashmir	12
10	Jharkhand	33
11	Karnataka	50
12	Kerala	36
13	Ladakh	12
14	Madhya Pradesh	43
15	Maharashtra	45
16	Manipur	34
17	Meghalaya	17
18	Mizoram	15
19	Nagaland	05
20	Odisha	62
21	Rajasthan	12
22	Sikkim	04
23	Tamil Nadu	36
24	Telangana	32
25	Tripura	19
26	Uttarakhand	05
27	Uttar Pradesh	15
28	West Bengal	40
29	Puducherry	01
30	Andaman & Nicobar	06
31	Dadar & Nagar Haveli	07
32	Daman & Diu	05
33	Lakshadweep	All inhabitants of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands who, and both of whose parents, were born in those islands.

APPENDIX 16. Contd.

the certificates are issued to the deserving persons it is necessary that proper verification be based primarily on revenue records and if need be, through reliable enquirers, is made before such certificates are issued. As it is only the Revenue Authorities who, besides having access to the relevant revenue records are in a position to make reliable enquiries, Government of India insists upon the production of certificates from such authorities only. In order to be competent to issue such certificate therefore the authorities mentioned in Appendix 15 of this brochure should be the one concerned with the locality in which the person applying for the certificate had his place of permanent abode at the time of the notification of the relevant Presidential Order. Thus the Revenue Authority of one District would not be competent to issue such a certificate in respect of persons belonging to another district. Nor can such an authority of one State/UT issue such a certificate in respect of persons whose place of permanent residence at the time of the notification of a particular Presidential Order has been in a different State/Union Territory. In the case of persons born after the date of notification of the relevant Presidential Order, the place of residence for the purpose of acquiring Scheduled Caste or Scheduled Tribes status is the place of permanent abode of their parents at the time of the notification of the Presidential Order under which they claim to belong to such a caste/tribe.



BROCHURE

02

Reservation for Scheduled Castes
and
Scheduled Tribes in Services

Sixth Edition

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATION
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
36/16/73-EST (SCIT)
NEW DELHI

For forms for issuance of the certificate of adoption, see Form No. 10, and for the certificate of adoption, see Form No. 11, and for the certificate of adoption, see Form No. 12.

(i) General (Applicable in all cases).

Where a person claims to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by birth, it should be verified:-

- (i) that the person and his parents actually belong to the community claimed;
- (ii) that this community is included in the Provincial Orders specifying the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the concerned State;
- (iii) that the person belongs to that State and to the area within that State in respect of which the community has been scheduled.

(iv) if the person claims to be a Scheduled Caste, he should profess either the Hindu or the Sikh religion;

(v) if the person claims to be a Scheduled Tribe, he must profess any religion.

(c) Cases of migration:

- (i) Where a person migrates from the portion of the State in respect of which his community is scheduled to another part of the same State in respect of which his community is not scheduled, he will continue to be deemed to be a member of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, as the case may be, in relation to that State;
- (ii) where a person migrates from one State to another, he can claim to belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe only in relation to the State to which he originally belonged and not in respect of the State to which he has migrated.

(d) Claims through marriages:

As a guiding principle it is that no person who was not a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by birth will be deemed to be a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe merely because he or she has married a person belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

Similarly a person who is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe will continue to be a member of that Scheduled Caste or Scheduled Tribe as the case may be, even after his or her marriage with a person who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(e) Cases of conversion and reconversion:

- (i) Where a Scheduled Caste person gets converted to a religion other than Hinduism or Sikhism and then reverts back to Hinduism or Sikhism, he will be deemed to have reverted to his original Scheduled Caste if he is accepted by the members of that particular caste as one among them.
- (ii) In the case of a descendant of a Scheduled Caste convert, the mere fact of conversion to Hinduism or Sikhism will not be sufficient to entitle him to be regarded as a member of the Scheduled Caste to which his forefathers belonged. It will have to be established that such a convert has been accepted by the members of the caste claimed, as one among themselves and has thus become a member of that caste.

(f) Cases of adoption:

On no case has to be exercised in dealing with cases where a person claims to be a Scheduled Caste on the ground that he has been adopted by a Scheduled Caste person.

The validity of an adoption has to be determined by the evidence submitted. The validity can be proved by the following:-

- (i) The requirements of valid adoption are given in sections 6 to 11 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. The actual giving and taking of the child in adoption is a mandatory requirement and thereafter the adopted child is deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes and the child ceases all ties with the family of his or her birth. Ordinarily, no child who has attained the age of 15 years or who is married can be given in adoption unless there is a custom or usage applicable to the parties.

(ii) In deciding whether an adoption is valid, the certificate issued by the authority should satisfy himself that all the requirements of law have been complied with. He should also take into account the behaviour of the child after adoption whether he is physically living with and is supported by his adoptive parents and receives no financial help from his original parents. In case these conditions are not satisfied, the certificate should be refused.

(iii) Where the case relates to an adoption of a married person of a person of the age of 15 years and above, the certificate shall be refused to be given by the District Magistrate who shall, after making due inquiries as to the validity of the adoption and as to whether such adoption is permitted by a custom or usage applicable to the parties, make an endorsement to that effect on the certificate. Such endorsement of usage should have been continuously and uniformly observed for a long time and of a kind the force of law among the Hindus of that particular area in that community group or family provided that the custom or usage is certain and not unreasonable or opposed to public policy and in the case of custom or usage, in respect of a particular family, that the custom or usage has been continuously observed. In addition, it should be verified that all other conditions for a valid adoption, including the provisions relating to the age of the adopted person, the age of the adoptive parent and that he has secured all ties with the original parents are fulfilled.

(iv) Clarification regarding the term "residence" for the purpose of the authority empowered to issue Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates (Ministry of Home Affairs circular letter No. 300, 10/25/76-SCTI, dated 21-3-1977).

As required under Articles 341 and 342 of the Constitution, the President has, with respect to every State and Union Territory and where it is State after consultation with the Governor of the concerned State, issued orders appointing various Caste and Tribes as Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory from time to time. The orders issued have been deliberately framed so that the people belonging to the specified community residing in a specified area, shall have been deemed to qualify for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe status, only if they have been accepted by the people belonging to the same caste or tribe in that area. Since the people belonging to the same caste or tribe, may not be such persons belonging to the same caste or tribe in different States or Union Territories, it is not to be understood in the literal or ordinary sense of the word, that the residence of a particular person in a particular locality assumes a special significance. This residence has not to be understood in the literal or ordinary sense of the word. On the other hand, it signifies the permanent residence of a person on the day of the notification of the Presidential Order appointing him as a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, as the case may be. It is not to be understood that a person, who is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, as the case may be, at the time of his appointment, shall continue to be a member of that caste or tribe in relation to the place of his temporary residence notwithstanding the fact that the name of his caste/tribe has been scheduled in respect of that area in any Presidential Order.

It is to ensure the veracity of this permanent residence of a person and that of his caste/tribe to which he claims to belong that the Government of India has made a special provision in the provision provided for the issue of such certificate. In effect, that

C. B. (II) No. 236

LOK SABHA

**THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED
TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

(Report of the Joint Committee)

[Presented on the 17th November, 1969]



**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

November, 1969/Kartika, 1891 (Saka)

Price : Rs. 2.30 P.

Published in the Gazette of India, (Extra.), Part II Sec. 3(ii), No. 333,
dated June 24, 1967/Asadha 3, 1889.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 24th June, 1967

S.O. 2138.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the
Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central
Government hereby makes the following further amendment to the
Imports and Exports (Control) Order, 1962, namely:—

1. In Part-B of Schedule I to the said Order after item No. 1(iii) (t),
the following items shall be added:—

(u) Butterflies,

(v) Moths larger than 75 mm."

2. In Part-A of Schedule I to the said Order, the following items
shall be deleted:—

(i) Butterflies;

(ii) Moths larger than 75 mm."

Published in the Gazette of India, Part II Sec. 3(i), No. 27,
dated July 8, 1967/Asadha 17, 1889

DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE

New Delhi, the 8th July, 1967

G.S.R. 1026.—In exercise of the powers conferred by section 37 of
the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Govern-
ment hereby makes the following rules further to amend the Central
Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (17th Amendment)
Rules, 1967.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 187, sub-rule (2) shall
be omitted.

Published in the Gazette of India, (Extra), Part II Sec. 3(i), No. 107,
dated June 24, 1967/Asadha 3, 1889

MINISTRY OF LAW

New Delhi, the 24th June, 1967

G.S.R. 960.—The following Order made by the President is publish-
ed for general information:—

Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of
the Constitution of India, the President, after consultation with the
Governor of the State of Uttar Pradesh, is pleased to make the following
Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes)
(Uttar Pradesh) Order, 1967.

2. The Tribes or tribal communities, or parts of, or groups within,
or tribal communities specified in the Schedule to this Order, shall,
for the purposes of the Constitution of India, be deemed to be Scheduled
Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards mem-
bers thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhotia, (2) Buksa, (3) Jaunsari, (4) Raji, (5) Tharu.

Published in the Gazette of India, (Extra.), Part II Sec. 3(ii), No. 337,
dated June 27, 1967/Asadha 6, 1889

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the 27th June, 1967

S.O. 2228.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5)

PART III—MANIPUR

1. Aimol.
2. Baite.
3. Chogthu.
4. Guite.
5. Kuki.
6. Puram.
7. Lusei (against Mizo).
8. Mikir.
9. Sukate.
10. Perum.
11. Ralte.
12. Sukte.
13. Kachanago (against Zamei-Licangmei).

PART IV—TRIPURA

1. Kalali, Karbong, Kaipeng, Dub, Thangchep, Sukuchep, Bengshel, Mussum, Murasing, Rankhal, Rupini, Lengui, Lengung.
2. Chaimal.
3. Kanda, Kheria, Kheriya.

CHAPTER V
UTTAR PRADESH

1. Shauka, Mana, Nitiwal (against Bhotia).
2. Bhil.

For the existing tribe 'Jaunsari (excluding Khasa Jaunsari, viz. Brahmin and Rajput)', the following tribes have been substituted :

3. Bajgi, Chanorm Beda, Turi, Nai Jhumaria, Auji, Darzi, Diyad, Dhake, Hurkiya.
4. Barhai, Badi, Mistri, Ode.
5. Chamar.
6. Chura.
7. Dhaliya.
8. Dom, Doom.
9. Jogi, Jogra, Nath.
10. Julaha, Varav.
11. Koli, Koi.
12. Kolta.
13. Kumhar.
14. Luhar.
15. Pari.
16. Ruriya.
17. Sunar.
18. Tamota.

of Jaunsar-Bawar Pargana in Dehradun District, Rawain Pargana in Uttar Kashi District and Jaunpur Pargana in Tehri Garhwal District.

Other Changes :

The spelling of 'Tolcha' has been corrected as 'Tolchha'.

purpose and period, the lessee shall cease to have any right, title or interest in the land or animal so let.

(2) Where any share of a holding has been let out under the proviso to clause expressing sub-section (1), the court may on the application of the asami or any tenure-holder determine the share of the lessor in the holding and partition the same.

[S. 158].

bhumidhar or asami [157-A. Restrictions on transfer of land by members of Scheduled Caste or Scheduled Tribe].—(1) Without prejudice to the restrictions contained in sections 153 to 157, no bhumidhar, [* * *] or asami belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall have the right to transfer by way of sale, gift, mortgage or lease any land to a person not belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe except with the previous approval of the Collector.

(Provided that a bhumidhar with transferable rights or asami belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe may, without such approval, transfer by way of mortgage without possession, his interest in any holding as security for a loan taken by way of financial assistance for agricultural purposes

defined in the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973) from the State Government by way of Taqavi, or from a co-operative land development bank, or from the State Bank of India or from any other bank which is a Scheduled Bank within the meaning of clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934, or from the U. P. State Agro-Industrial Corporation limited in clause (c) or (d) of the said Act];

(2) On an application being given in that behalf in the prescribed manner, the Collector shall make such inquiries as may be prescribed.

⁷ Explanation.—In this Chapter, the expressions 'Scheduled Castes' and 'Scheduled Tribes' respectively mean the Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified in relation to Uttar Pradesh under Articles 341 and 342 of the Constitution.]

158. Registration of a lease.—Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Act IV of 1882) or the Indian Registration Act, 1908 (Act XVI of 1908), a lease for a term exceeding one year or from year to year may be made either by a registered instrument or in the prescribed manner.

in clause (c) of section 2 of the Act, 1934, acquires any land the whole or part of such land and after the expiry of

1. Added by section 37 of U. P. Act XVI of 1953 with effect from its commencement i. e. June 16, 1953 and omitted by U. P. Act 30 of 1975.
2. Ins. by section 9 of U. P. Act IV of 1969, and prior to that added by section 5 of U. P. Ordinance No. III of 1969 (with effect from June 3, 1969).

NOTE.—For U. P., the President of India has declared (1) Tharu, (2) Buksa, (3) Bhotia, (4) Jaunsari, and (5) Raji as Scheduled Tribes, vide G. O. No. 174/I-A-3-1 (1)-69, dated June 19, 1969.

3. Subs. by section 7 of U. P. Act 34 of 1974 for the words 'Scheduled Tribe.'
4. Omitted by U. P. Act 8 of 1977 (w. e. f. 28-1-1977).
5. Ins. by U. P. Act 34 of 1974.
6. Subs. by U. P. Act 8 of 1977 (w. e. f. 28-1-1977).
7. Subs. by ibid.

P. Act 34 of 1974, Also see section

(a) of section 133 by section 7 of the Act, 1953, with effect from its commencement, i. e. June 16, 1953.

Act XX of 1954.

X of 1954.

by section 15 of U. P. Act 30 of 1975.

APPENDIX VII—Contd.

S. No.	Tribe	Synonym	Sub-tribe
24.	KHARWAR	..	..
25.	KOLHA-LOHARA	MUNDA-LOHARA	..
26.	KONDA DHORA	..	..
27.	KORA	..	..
28.	KORWA	..	..
29.	KOYA	..	GANDIA MADIA
30.	LODHA	..	..
31.	MAHALI	..	..
32.	MALHAR KOLI	..	..
33.	MATYA	..	..
34.	MIRDHA	..	..
35.	MUNDA	MUNDARI THARUA	..
36.	NAGESIA	KISAN	..
37.	OMANATYA	..	..
38.	ORAO	URAM	..
39.	PARAJA	..	..
40.	PARENGA	..	..
41.	PENTIA	..	..
42.	RAJUAR	..	..
43.	SANTAL	..	..
44.	SAURA	SAHARA SAORA SAYAR SHABAR	..
		PUNJAB	..
1.	BETA	..	..
2.	BODH.	..	..
3.	CHAN	..	..
4.	DOMBA	GARA ZOA	..
5.	KANET (of Chota and Bara Banghal)	SEOK	..
6.	SWANGLA	..	..

APPENDIX VII—Contd.

S. No.	Tribe	Synonym	Sub-tribe
		RAJASTHAN	
1.	BHIL	BHIL MINA GAMETI	..
2.	CHOWKIDAR MINA	..	..
3.	DAMOR	DAMARIA	..
4.	GARASIA	..	..
5.	KATHODI	..	..
6.	SEHARIA	..	..
		UTTAR PRADESH	
1.	AGARIA	..	..
2.	BAIGA	..	..
3.	BHOTIA	BHOTA JAUHARIA MARCHHA TOLERA JAD	..
4.	BHUNIYA	BHUTYAR	..
5.	BUKSA	..	..
6.	CHERO	..	..
7.	GOND	..	DHURIYA NAYAK OJHA PATHARI RAUGOND
8.	JAUNSARI (excluding KHASA JAUN- SARI, Wz. Brahmin and Rajput)	..	..
9.	KHAIRWAR	..	..
10.	KORWA (of the Mirza- pur district south of the Kaimur range)	..	..
11.	KOL	..	..
12.	MAJHWAR	..	..
13.	ORAO (of the Mirza- pur district south of the Kaimur range)	..	..

APPENDIX IV—contd.

Community	Reason for inclusion
B. SCHEDULED TRIBES	
<i>Jammu & Kashmir</i>	
1. CHAMPA	A tribal community living in the Chushul area of Ladakh. Has tribal characteristics, and is very isolated. Population about 1000.
<i>Kerala</i>	
2. ALLAR	They are a very primitive tribe of food gatherers and are still living in caves. Population about 300.
3. KANALADI or KALANADI	This tribe is found in Wynad, and number about 350. They are primitive, and live far removed from centres of educational and industrial development.
4. KUNDUVADIYAN	This is a small tribe inhabiting the forest areas of Wynad. Their population is about 500.
5. MALA ADIYAN	This is a primitive section of the KURAVANS, inhabiting the Wynad area. Population about 6000.
6. MALAKKARAN or MALAMUTTAN or MALAPANICKAR.	Jungle cultivators and hunters in the Wynad area. Population about 1000.
7. MALA VETTUVAN	A primitive jungle tribe, living in difficult and isolated conditions in the Wynad area. Population about 3500.
8. PATHIYAN	A small tribe residing in Eastern Wynad. Have tribal characteristics and are isolated. Population about 300.
<i>Madras</i>	
9. NARIKORAVAN or KURIVIKKARAN.	A very backward tribe, with distinctive dress and customs. Population about 3500.
<i>Punjab</i>	
10. BETA 11. CHAN 12. DOMBA or GARA or ZOBA	These communities are living in the isolated tribal areas of Lahaul and Spiti and their way of life and customs resemble those of the tribal folk. Population about 1,400.

APPENDIX IV—contd.

Community	Reasons for inclusion
13. KANET (of Chhota and Bara Banghal) or SEOK	They are isolated tribal community. The social customs are distinctive, and they engage in primitive type of agriculture and sheep rearing. Population about 5,000.
<i>Uttar Pradesh</i>	
14. BHOTIA	They live in the isolated border areas, and have a distinct tribal organization. Estimated population 12,000.
15. BUKSA	A tribal group found in the Naini Tal Terai. They number about 10,000 and are primitive.
16. JAUNSARI	A polyandrous tribal group residing in the Dehra Dun, Tehri Garhwal and Uttarakhand districts. They are isolated, and backward. There are however some forward groups, viz. Baimins and Rajputs, who are being assimilated. Estimated population 56,000.
17. THARU	A distinct tribe of the Tehri Belt of Uttar Pradesh. They are very primitive. Estimated population 44,000.
18. RAJI	This is a more common name for BANMANUS, hitherto treated as a Scheduled Caste.
19. ORAON	The tribal DHANGARS of Mirzapur district are a section of the ORAONS. DHANGAR is presently included in the list of Scheduled Castes.

groups and removal of the area restrictions for the hills and plains tribes; he was, however, unable to commit his Government to these views.

43. In view of this highly complex situation, the Committee has been obliged to revise and coordinate the lists on the basis of available facts rather than ideological considerations.

Rejections

44. We had to reject certain proposals for inclusion of some castes and tribes in the lists. A list of such castes and tribes appears at Appendix VI. We are not satisfied, for various reasons, that these castes and tribes should be given a place in the lists.

Revised Lists

44-A. The complete list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as revised by us, appears at Appendix VII.

Effect on Population

45. We have tried to assess the effect of our revision of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on their recorded population. According to the 1961 Census, the population of Scheduled Castes was approximately 65 millions and that of the Scheduled Tribes about 30 millions. (Incidentally, both these together constitute over 21 per cent of the total population of India.) After taking into consideration the population of castes and tribes excluded from the revised lists, and on an estimate of the population of castes and tribes added to these lists, there will not be any appreciable change in the population of the Scheduled Castes, while the population of Scheduled Tribes will increase by a little less than two millions.

CHAPTER IV

GENERAL RECOMMENDATIONS

46. In revising the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes we have excluded some castes and tribes. These excluded castes and tribes are already enjoying certain educational, economic and other developmental benefits. We are of the view that they should not be deprived of these benefits abruptly; in particular, we consider that members of these castes and tribes who are participating in scholarship schemes should not be suddenly denied their education. We would recommend that the benefits enjoyed by the excluded castes and tribes should be gradually withdrawn in a phased manner.

47. There are some communities which, though not strictly eligible to be treated as Scheduled Castes and Scheduled Tribes, deserve special assistance. It would not be sufficient to treat them merely as "Other Backward Classes" as they require larger aid than is provided to Other Backward Classes. The communities which we have in mind are the Gujjar, Gaddi and Banjara communities.

48. In the course of the revision of the lists, we have at times adopted local names and synonyms and altered the spelling of some castes and tribes. These nominal changes should not affect continuation of privileges and benefits to those castes and tribes subjected to such changes. It would be for the State Governments to ensure that the castes and tribes whose names are altered in the revised list are not denied the benefits they were previously entitled to. The State Governments should be advised to issue necessary instructions to the appropriate authorities.

49. We have advised that where a caste or a tribe is mentioned in the lists by its generic name, it should be deemed to include all its synonyms, phonetic variations, sub-castes or sub-tribes, as the case may be. We have no doubt enumerated in some cases the sub-castes and sub-tribes but such an enumeration is imperfect and is not exhaustive for want of complete data. The State Governments should collect the necessary information and

THE REPORT
OF THE
ADVISORY COMMITTEE
ON THE
REVISION OF THE LISTS OF
SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES



GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

New Delhi 25 Aug 1965
Chairman B.N. - LOKUR

(36) AS INTRODUCED IN LOK SABHA ON

12 AUG 1967. (6)

Bill No. 119 of 1967

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

A
BILL

to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation, and re-delimitation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment and re-delimitation are necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1967.

Short
title and
com-
mence-
ment.

be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards members thereof resident in that State.";

(b) for the Schedule, substitute—

5.

"THE SCHEDULE

UTTAR PRADESH

	Tribe	Synonym	Sub-tribe
	1	2	3
	1. Agaria		
10	2. Baiga		
	3. Bhotia	Bhota	
		Jauharia	
		Marchha	
		Toleha	
15		Jad	
	4. Bhuinya	Bhuiyar	
	5. Buksa		
	6. Chero		
20	7. Gond		Dhuriya
			Nayak
			Ojha
			Pathari
			Rajgond
25	8. Jaunsari (excluding Khasa Jaunsari, viz., Brahmin and Rajput)		
	9. Khairwar		
30	10. Korwa (of the Mirzapur district south of the Kaimur range).		
	11. Kol		
	12. Majhwar		
35	13. Oraon Dhangar (of the Mirzapur district south of the Kaimur range).		
	14. Parahiya	Parahaiya	
	15. Raji	Banrawat	
		Banmanus	
	16. Saharia		Saharia Rawat
40	17. Tharu		"

SAB 24 (17)

8

NO.12016/27/2001-TA(RL)
Government of India
Ministry of Tribal Affairs

Shastri Bhawan, New Delhi
23 February, 2004

To

The Secretary
Social Welfare Department
Govt. of Uttaranchal
Dehradun

Subject: Revision of List of STs in the State of Uttaranchal

Sir,

I am directed to refer to the d.o. letter of even number dated 10.9.2001 from Shri S. Chatterjee, Joint Secretary in this Ministry on the above subject (copy enclosed) and to say that the requisite information/recommendation from the State Government of Uttaranchal is still awaited. The proposal is under active consideration of this Ministry in view of Hon'ble Prime Minister's address at Dehradun on 28.1.2004. The copy of the extract of PM's Address at Dehradun in this matter is enclosed.

It is, therefore, requested to kindly arrange to furnish the requisite information/recommendation of your State to this Ministry at the earliest.

Yours faithfully,

(Dr. N.K. Ghatak)
Joint Director



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
जनजातीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001
टेलीफोन : 3383622
फैक्स : 3073607

D.O. NO. 12016/27/2001-TA(RL)

SLN-4(L)

10.09.2001

Dear Ms. Veereta,

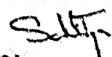
Please refer to Letter No. 12016/36/96-SCD(R.Cell) dated 15.12.2000 addressed to your Chief Secretary by the Ministry of Social Justice & Empowerment and your d.o. letter No. 1312/FRDC/2001 dated 28.08.2001 regarding revision of list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

2. As you are aware from October, 1999 a new Ministry of Tribal Affairs have been created for looking after the affairs of tribal development. Therefore, the Ministry of Tribal Affairs is now the nodal agency for the issue of specification of communities as Scheduled Tribes. The Ministry has examined the proposals and it has been found that while recommending inclusion of certain communities the State Government has not furnished specific information on the proposal duly supported by ethnographic material for processing cases as per approved modalities. A statement showing observations of this Ministry on the proposals is enclosed.

3. As the matter has been pending for a very long time, I shall be grateful if you could kindly look into the matter personally and send specific details at the earliest.

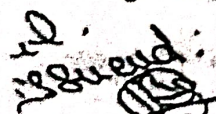
With regards,

Yours sincerely,


(S. Chatterjee)

✓ Smt. Veereta Kumar,
Secretary,
Social Welfare Department,
Government of Uttaranchal,
Dehradun. 0135-712114

✓ Encl: as above.


12/9/2001

Details of proposals

Community	Proposal	Remarks
Jaunsari	Modification in ST list Instead of Jaunsari the following tribes of Jaunsar, Bawar, Pargana in Dehra Dun Distt. Rawain Pargana in Uttar Kashi Distt. and Jaunsari in Tehri Garhwal Distt. may be substituted a) Bajgi, Auji, Chanao, Beda, Darzi/Darji, Dhake, Diad, Hurkiya, Turi, Nai, Jhumaria, Barhai/Badi/Mistri/Ode b) Chamar c) Chura d) Dhaliya e) Dom/Doome f) Jogi/Jogra/Nath g) Julaha, Waro h) Koli/Koi i) Kolta j) Kumhar k) Lchar l) Pari m) Ruriya n) Sunar o) Tomota	The Govt. of Uttar Pradesh under its letter dated May 1981 had recommended modification to the effect that instead of Jaunsari the following tribes of Jaunsar, Bawar, Pargana in Dehra Dun Distt. Rawain Pargana in Uttar Kashi Distt. and Jaunpur Pargana in Tehri Garhwal Distt. may be substituted a) Bajgi, Auji, Chanao, Beda, Darzi/Darji, Dhake, Diad, Hurkiya, Turi, Nai, Jhumaria, Barhai/Badi/Mistri/Ode b) Chamar c) Chura d) Dhaliya e) Dom/Doome f) Jogi/Jogra/Nath g) Julaha, Waro h) Koli/Koi i) Kolta j) Kumhar k) Lohar l) Pari m) Ruriya n) Sunar o) Tomota The Govt. of Uttaranchal under its letter dated 28.8.2001 has inter-alia suggested that the original entry may be retained. In this connection it is stated that the provisions of Article 342 of the Constitution envisage notification of ethnic groups as Scheduled Tribes. The present entry Jaunsari is not an ethnic group rather it is a territorial name which encompasses various communities which are not equally backward. The Lokur Committee in its report submitted in 1965 had suggested exclusion of Khasa Jaunsaris viz. Rajputs and Brahmins who are relatively advanced sections. Further, some of the communities of Jaunsaris such as Bajgi, Badi, Chamar and Dom are treated ST as well as SC in relation to Jaunsar area of the State. Similarly, Sunar and Darji are treated as OBC as well as ST. In order to remove the above anomalies it is necessary that the Jaunsari entry may be modified by keeping out more advanced ethno cultural groups. State Govt. is requested to indicate specific ethnic groups by excluding advanced ethno cultural groups among Jaunsaris to enable more socially and economically backward groups to drive benefits more for them.

	Ranwala/Jaunpuri	Inclusion in ST list	The State Govt. under its letter dated 28.8.2001 has recommended specification of Ranwalias and Jaunpuris as Scheduled Tribes in relation to the State of Uttranchal but both these terms are territorial names. The State Govt. is requested to indicate name of specific ethnic groups which may be included in the list. The observation made in respect of Jaunsari also holds good in respect of this entry.
3.	Residents of Mansiari and Dharchula tehsils of Pithoragarh Distt.	Inclusion in ST list.	The State Govt. is requested to furnish its recommendation as required under Article 342. The proposed entry is also a territorial name.

सिद्धि निर्यात - Nos 11
सिद्धि निर्यात Joint Committee - 4

Shyam Lal Johar

12

C. B. (II) No. 236

LOK SABHA

**THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED
TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

(Report of the Joint Committee)

[Presented on the 17th November, 1969]



**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

November, 1969 (S. 111, 1967 (S. 111))

Price : Rs. 1.30 P.

Bill No. 119-B of 1967

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

(AS REPORTED BY THE JOINT COMMITTEE)

(Words side-lined or underlined indicate the amendments suggested
by the Committee; asterisks indicate omissions.)

A
BILL

to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation, and re-delimitation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment and re-delimitation are necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Twentieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1969.

5 (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "census authority" means the Registrar General and ex officio Census Commissioner for India;

10 (b) "Commission" means the Election Commission appointed by the President under article 324 of the Constitution;

(c) "former Act" means the Delimitation Commission Act, 1962;

Short
title and
com-
mence-
ment.

Defini-
tions.

2A. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person, who has given up tribal faith or faiths and has embraced either Christianity or Islam, shall be deemed to be a member of any Scheduled Tribe.”;

(b) for the Schedule, substitute—

“THE SCHEDULE

UTTAR PRADESH

1. Agarla
2. Baiga
3. Bhil
4. Bhotia; Bhotia, Jad, Jauharia, Mana, Marchha, Nitiwal, Shauka, Tolchha
5. Bhuiya; Bhuiyar
6. Buksa
7. Chero
8. Gond; Dhuriya, Nayak, Ojha, Pathari, Rajgond
9. Khairwar
10. Korwa (in the Mirzapur district south of the Kaimur range)
11. Kol
12. Majhwar
13. Oraon Dhangar (in the Mirzapur district south of the Kaimur range)
14. Parahiya; Parahaiya
15. Raji; Banrawat, Banmanus
16. Saharia; Saharia Rawat
17. Tharu.

The following tribes of Jaunsar-Bawar Pargana in Dehradun District, Rawain Pargana in Uttar Kashi District and Jaunpur Pargana in Tehri Garhwal District:—

18. Bajgi; Auji, Chanorm Beda, Darzi, Dhake, Diyad, Hurkiya, Turi, Nai Jhumaria
19. Barhai; Badi, Mistri, Ode
20. Chamar
21. Chura
22. Dhaliya
23. Dom; Doom
24. Jogi; Jogra, Nath
25. Julaha; Varav
26. Koli; Koi
27. Kolta
28. Kumhar
29. Luhar
30. Pari
31. Ruriya
32. Sunar
33. Tamota.”

PART III—MANIPUR

1. Aimol.
2. Baite.
3. Chogthu.
4. Guite.
5. Kuki.
6. Puram.
7. Lusci (against Mizo).
8. Mikir.
9. Sukate.
10. Perum.
11. Ralte.
12. Sukte.
13. Kachanago (against Zamei-Lieangmei).

PART IV—TRIPURA

1. Kalali, Karbong, Kaibeng, Dub, Thangchep, Sukuchep, Bengshel, Mussum, Murasing, Rankhal, Rupini, Lengui, Lengung.
2. Chaimal.
3. Kanda, Kheria, Kheriya.

CHAPTER V
UTTAR PRADESH

1. Shauka, Mana, Nitiwal (against Bhoira).
2. Bhil.

For the existing tribe Jaunsari (excluding Khasa, Jaunsari, viz. Baram and Rajpur), the following tribes have been substituted:

3. Bajgi, Chanorm, Beda, Turi, Nai, Jhumaria, Auji, Darzi, Diyad, Dhake, Hurkiya.
4. Barhai, Badi, Mistri, Ode.
5. Chamar.
6. Chura.
7. Dhaliya.
8. Dom, Dood.
9. Jogi, Jogra, Nath.
10. Julaha, Varay.
11. Koli, Koi.
12. Kola.
13. Kurhar.
14. Luhar.
15. Pari.
16. Ruziya.
17. Sunar.
18. Tameta.

of Jaunsar-Bawar Pargana
Dehradun District, Raw.
Pargana in Uttar Kashi Distr
and Jaunsar Pargana in
Garhwal District.

Other Changes :

The spelling of 'Tolcha' has been corrected
as 'Tolchha'.